घोटालों की मांद है नगर निगम, पेरीफेरल रोड निर्माण में करोड़ों के घोटाले

फ़रीदाबाद (म.मो.) पेरीफेरल रोड यानी बीके चौक से हार्डवेयर चौक, बाटा चौक, नीलम चौक, एनआईटी थाना के गोल चक्कर से केसी रोड होते हुए बीके चौक तक की सड़क को चौड़ा करने, फुटपाथ व साइकिल ट्रैक तथा सड़क के डिवाइडर में पेड़-पौधे व ग्रील आदि लगाने के साथ-साथ स्ट्रीट लाइट तथा जल निकासी का काम कराने की घोषणा 2017-18 में मुख्यमंत्री खट्टर ने की थी। उनके आदेश पर 76 करोड़ का एस्टीमेट तैयार करके आरके गांधी ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया।

हेरा-फेरी में मास्टर गांधी निगम के लुटेरे अधिकारियों को खूब भाता है। सड़क निर्माण के लिये टेंडर भरने में अनेक प्रकार के सम्बन्धित कामों के लिये अलग-अलग रेट भरे जाते हैं। गांधी जैसे खिलाड़ी ठेकेदार उन कामों के रेट बहुत ही कम भरता है जो उसे करने ही नहीं होते और जो करने होते हैं उनके रेट अच्छे-खासे भरता है।

राजकुमार गांधी : विजिलेंस की आई जांच तो हो गए स्वर्गवासी

इसके चलते उसका टेंडर सस्ता होने के नाते पास हो जाता है। कुल काम का करीब 80-90 प्रतिशत पूरा करके अपनी पेमेंट लेकर पार हो जाता है और बाकी के काम जो उसे करने नहीं होते उन्हें छोड़ जाता।

एस्टीमेट की रकम बढ़वाने के लिये दूसरी ट्रिक घोषित किये गये काम में संशोधन करने की होती है। मूल रूप से इस पेरीफेरल रोड को तारकोल से बनाना था लेकिन लूट कमाई को बढ़ाने के लिये एस्टीमेट में संशोधन करके इसे सीमेंट कर दिया गया और लागत बढ़ाकर 102 करोड़ कर दी गई। विदित है कि इतने बड़े एस्टीमेट को पास करने का अधिकार निगमायुक्त को नहीं होता। इसकी स्वीकृति चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेनी होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई थी।

पिछले दिनों थाना एनआईटी के सामने वाले गोल चक्कर में मूर्ति स्थापना की नौटंकी करते हुए स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा ने मौके पर मौजूद निगम अधिकारियों पर अहसान जताते हुए कह भी दिया कि उन्होंने सड़क को तारकोल की बजाय सीमेंट से बनवाने का जिम्मा अपने ऊपर लेकर उनकी आफ़त टलवा दी। टलवाये भी क्यों न उनकी लूट में सीमा का भी तो हिस्सा रहता ही है।

इस सड़क में एक यही अनियमितता नहीं है, टेंडर के अनुसार जो फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी, व सड़कों के बीच में पेड़-पौधे व ग्रिल आदि का काम भी पूरा नहीं किया गया। अब और कोई ठेकेदार इन कामों को उस रेट में कर ही नहीं सकता जो गांधी ने एक ट्रिक के तौर पर टेंडर में भरे थे। इसलिये इन कामों के होने की अब कोई सम्भावना नजर नहीं आती। इसी सड़क का यही सारा काम 2011-12 में शकील हैदर ठेकेदार को कम रेट के आधार पर मिल गया। ठेका तो मिल गया परन्तु निगम अधिकारी इससे खुश नहीं थे। इसलिये उसको काम में सहयोग देने की बजाय अड़चने खड़ी करने लगे थे। परिणामस्वरूप वह भी आधा-अधूरा काम छोड़ कर चला गया।

दूसरा बड़ा गजब स्मार्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड के बनने से हो गया। खट्टर सरकार की इस कम्पनी ने भी इसी सड़क के कुछ हिस्सों के लिये टेंडर जारी कर दिये। निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। इसके तहत थाना एनआईटी से नीलम चौक तक फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी के लिये नाले आदि बनाने का काम सौंपा गया। इसी टेंडर में थाना एनआईटी से लेकर कोढ़ी कॉलोनी से होते हुए शमशान घाट तक की सड़क पर भी यही सब काम होने वाले थे जो लगभग पूरे भी हो चुके हैं। यहां घोटाला डबल टेंडर का हो गया। यानी कि जिस काम का टेंडर नगर निगम दे चुका था उसी काम का टेंडर स्मार्ट सिटी ने भी दे दिया। इससे पहले कि दोनों टेंडरों की पेमेंट हो जाती, कुछ जागरूक नागरिकों ने इसकी सूचना स्मार्ट सिटी कम्पनी की मुखिया गरिमा मित्तल आईएएस को दे दी। मामले की जांच जारी है।

वैसे डबल टेंडरी का यह कोई, इकलौता मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले यहां दबे पड़े हैं।

शिक्षानाश का अभियान तेज़ किया, खट्टर सरकार के विरोध में उतरे ग्रामीण

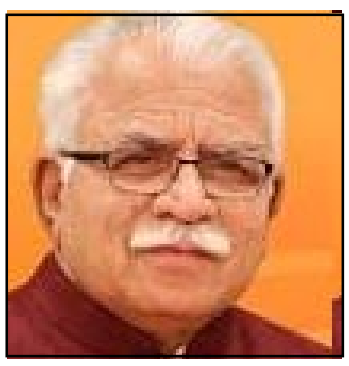

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

जनता को शिक्षा से वंचित रखने के लिये सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान में इस सप्ताह यकायक उस समय तेजी आ गई जब सरकार ने रोहतक, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, झज्जर, सोनीपत आदि जिलों के 105 स्कूलों को बंद करने का एलान किया। इस एलान को सरकार स्कूलों का बंद करना न कह कर समाहित करना बता रही है। यानी कि सरकार सीधे-सीधे बंद करने का साहस नहीं जुटा पा रही। लेकिन ग्रामीण खट्टर की घोषणा को सही से समझ चुके हैं। इसी के चलते ग्रामीणों ने अपने-अपने गांवों के स्कूलों में ताले जड़ दिये हैं। कुछ स्कूलों में तो विरोधस्वरूप स्टाफ़ को भी भीतर ही बंद कर दिया।

जहां एक ओर सरकार जनता के खून-पसीने से टैक्स पर टैक्स वसूलने में जुटी है, वहीं जनता को मिलने वाली हर तरह की सुविधा एवं सेवायें हड़पने में लगी है। बुढापा पेंशन तथा विकलांगों को मिलने वाली सुविधाओं में भारी कटौती तो सरकार कर ही रही थी, शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी सरकार और अधिक वहन नहीं करना चाहती। इसी नीयत से तमाम सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में हजारों शिक्षकों के पद खाली रखे हुए हैं। जिस स्कूल में शिक्षक ही नही होंगे तो बच्चे काहे को वहां दाखिला लेंगे ?

ढोंग बिखेरने के लिये सरकार हर साल अधिक से अधिक बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिल करने का अभियान चलाती है। इस अभियान में केवल वही वंचित एवं मजबूर लोग फंसते हैं जिनके पास निजी स्कूलों की फ़ीस भरने की क्षमता न हो। जाहिर है ऐसे में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घटती जाती है। इसी घटती संख्या के बहाने सरकार स्कूलों को बंद करती जाती है।

जानकारों के अनुसार सरकार का छिपा एजेंडा तमाम सरकारी स्कूलों को निजी शिक्षा व्यापारियों के हाथों बेच खाने का है। जिस तरह से मोदी की केन्द्र सरकार एक-एक करके तमाम सरकारी उपक्रमों को औने-पौने में अपने कार्पोरेट मित्रों को बेच रही है, उसी तर्ज पर खट्टर भी अपने अधिकार क्षेत्र के तमाम उपक्रमों पर गिद्ध दृष्टि जमाये बैठे हैं।

इसके अलावा सरकार का दूसरा उद्देश्य, जहां तक संभव हो सके जनता को अनपढ़ रखना है। वे समझते हैं कि पढ़-लिखने के बाद एक तो उनकी बुद्धि का बेहतर विकास हो जाता है जिसके चलते वे अपने अधिकारों को समझ कर सरकार पर सवाल खड़े करने लगते हैं। दूसरे, पढ़े-लिखे युवक नौकरी की मांग करने लगते हैं। इन दोनों आपदाओं से बचने के लिये जनता को अनपढ़ रखना ही बेहतर होगा।

गलियों में भरे सीवेज से परेशान 2 नम्बर डी ब्लॉक निवासियों ने किया प्रदर्शन

रजनीश ढींगड़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहरों में जल-मल एवं सफ़ाई की आधुनिक व्यवस्था के तौर पर सीवरेज प्रणाली को विकसित किया गया। परन्तु आज यह व्यवस्था शहरवासियों के लिये बड़ी समस्या बन कर रह गई है।

इस शहर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां पर सीवरेज से उफ़न कर गंदा पानी सड़कों पर न फैलता हो। लेकिन एनआईटी के नम्बर 1,2,3, व 5 में तो इसका प्रकोप कुछ ज्यादा ही है। इस मुद्दे पर कच्ची कॉलोनियों की बात न ही की जाये तो बेहतर है। एनएच 2 के डी ब्लॉक में तो पिछले कई हफ्तों से सीवर का सड़ा पानी गलियों में इस कदर भरा रहा कि लोगों का आना-जाना दूभर हो गया। बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी जब नगर निगम वालों ने कोई सुध न ली तो निवासियों को बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। वैसे इस तरह के प्रदर्शन व रोड जाम ये लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। इस तरह के प्रदर्शन के बाद निगम की ओर से सकर मशीन आती है और सड़े पानी को निकाल कर ले जाती है। डी ब्लॉक वासियों के प्रदर्शन के बाद सोमवार 22 तारीख को वहां भी मशीन आई और गंदे पानी को भर कर ले गई।

समस्या का यह कोई स्थायी हल नहीं है। दो दिन बाद नहीं तो चार दिन बाद फ़िर वही स्थिति बनने वाली है। स्थायी हल तो केवल सीवेरेज व्यवस्था को सुचारु करने से ही हो सकता है जो कि इस निगम प्रशासन के बस का नहीं है। प्रदर्शनकारी अपने पार्षद व मेयर को कोस रहे थे। वे निगमायुक्त को भी मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सीवरेज समस्या इस कदर बिगाड़ दी गई है कि पार्षद और मेयर तो क्या निगमायुक्त के भी काबू की नहीं रह गई है।

जितने घरों व आबादी के लिये यह व्यवस्था बनाई गई थी उससे कई गुणा ज्यादा घर व आबादी का बोझ इस पर डाल दिया गया है। इसके लिये नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों तथा राजनेताओं द्वारा करवाये गये अवैध कब्जे व अवैध निर्माण जिम्मेवार हैं। कोढ़ में खाज का काम करते अनपढ़ एवं भ्रष्ट योजनाकार तथा इंजीनियर हैं। इन तमाम हालातों के लिये किसी एक अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिये पूरा सरकारी तंत्र उत्तरदायी है। रही बात पार्षदों व मेयर की तो इन लोगों ने भी इस भ्रष्ट तंत्र के विरुद्ध कभी आवाज बुलंद करने की अपेक्षा लूट कमाई में हिस्सेदारी करना बेहतर समझा।

बीते कई वर्षों से नाकारा हुए पड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) को अब नये सिरे से बनाने की योजनायें बनाई जा रही हैं, ये प्लांट कब बनेंगे कोई नहीं जानता। हां, हाल-फिलहाल में एक नया कन्सेप्ट, पार्कों में छोटे एसटीपी लगाने का आ गया है। इनके द्वारा एक क्षेत्र विशेष के सीवेज का शोधित पानी पार्कों में छोड़ा जायेगा।

नगर निगम की कार्यशैली एवं क्षमता को जानने वाले भलीभांति समझते हैं कि इनके लगाये हुए एसटीपी कभी चलने वाले नहीं होंगे। लिहाजा सारा सीवेज इन पार्कों में सड़ा करेगा।